मुकेश आडवाणी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

2 मई, 1985

[डी.ए. देसाई और ए. वरदराजन, जेजे.]

सामाजिक कार्रवाई मुकदमा-खनन ठेकेदारों द्वारा तमिलनाडु के श्रमिकों का शोषण-गरीब और जरूरतमंद मजदूरों की राज्य सुरक्षा की आवश्यकता है जो समानता की शर्तों पर बातचीत करने में असमर्थ हैं, भारत के संविधान, 1950 ने दोहराया। अनुच्छेद 38,41,42,43, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1974-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965।

14 सितंबर, 1982 को "इंडियन एक्सप्रेस" में एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से एक को संबोधित किया, जिसमें मध्य प्रदेश के रायसेन में पत्थर की खदानों में काम करने वाले तमिलनाडु के बंधुआ श्रमिकों की भयावह दुर्दशा को दर्शाया गया था। आरोप लगाया गया थाः (क) भर्ती किए गए सभी लोगों को रुपये 1,000/की प्रतिपूर्ति योग्य अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था। लेकिन लेखांकन की विधि में इतना हेरफेर किया गया है कि ऋण समाप्त होने के बजाय, ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि हुई है और किसी भी श्रमिक को तब तक रोजगार नहीं मिल सकता है जब तक कि पूरे ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है जो श्रमिकों की पहुंच से बाहर है; (बी) काम करने की स्थिति खराब थी। कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं था। स्वच्छता की स्थिति दयनीय

स्थिति में थी। बरसात के मौसम में श्रमिकों को कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, क्योंकि खदानें बंद हो गई थीं; (ग) श्रम कल्याण के लिए अधिनियमित एक भी कानून को लागू या सम्मानित नहीं किया जाता है और (घ) केंद्र और राज्य के श्रम विभाग की निष्क्रियता के कारण खानों में कार्यरत श्रम बल के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना के अभाव के कारण, जिसके परिणामस्वरूप कम और कम भुगतान होता है, श्रमिकों का नग्न और निर्लज्ज शोषण होता है। जिला न्यायाधीश भोपाल से उच्चतम न्यायालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट ने उक्त आरोपों की पुष्टि की और आगे खुलासा किया कि (ए) एक शिकायत पर मध्य प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा 48 श्रमिकों को रिहा कर दिया गया था; (बी) बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है; (सी) ठेकेदारों के खिलाफ दो या तीन मामले वास्तव में दर्ज किए गए थे और उक्त मामले दर्ज किए गए थे। (घ) एक मानक 'खांटी' खोदने के लिए मजदूरी का भुगतान करने की दर-दर विधि के परिणामस्वरूप कुछ समय के लिए नियोजित पुरुष और महिला श्रम दोनों के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है; (ङ) पुलिस बल की एक टीम तमिलनाडु से आई और श्रमिकों को मुक्त किया और उन्हें तमिलनाडु वापस भेज दिया और (च) समाचार पत्र के प्रचार का बहुत ही लाभकारी और वांछित प्रभाव पड़ा। विभिन्न ठेकेदारों ने अग्रिम राशि की वसूली के प्रयास छोड़ दिए हैं जो एक अच्छी उपलब्धि थी।

मध्य प्रदेश राज्य ने जिला न्यायाधीश, भोपाल के निष्कर्षों को स्वीकार किया और बताया कि फ्लैगस्टोन खदानों के संबंध में भुगतान के तहत केंद्र सरकार उपयुक्त है। बोनस अधिनियम, 1965 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों को कैसे ठगा गया और मध्य प्रदेश ले जाया गया और उनके राज्य पुलिस द्वारा मजदूरों की रिहाई की पुष्टि की गई है।

अदालत ने परिस्थितियों में भारत संघ को मंजूरी के रूप में निर्देश दिया सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें व्यक्तियों की जानकारी के लिए अपने प्रस्ताव को निर्धारित किया जाएगा। इससे प्रभावित होने की संभावना है और अधिसूचना की तारीख से कम से कम दो महीने की तारीख निर्दिष्ट की जाएगी जिस पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। भारत संघ ने तदनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी की दिनांक 24 मार्च, 1982 और 31 अक्टूबर, 1983 को न्यूनतम टुकड़ा दर निर्धारित की गई फ्लैगस्टोन खदानों में विभिन्न व्यवसायों के लिए मजदूरी।

न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

1. निस्संदेह, राष्ट्रीय हित के खदानों को बड़े पैमाने पर काम करना पड़ता है और। इसलिए, चीजों की प्रकृति में, ठेकेदारों और कर्मचारी विरोधाभास होगा। ठेकेदार जैसा कि उसकी आदत है, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए जो उसे अनुबंध लेने के लिए प्रेरित करता है और जिसे परोपकारी नहीं दिखाया जाता है, कामगारों का शोषण करने के लिए बाध्य है। शोषण का कुख्यात तरीका है, न्यूनतम मजदूरी के सभी ढोंग के बावजूद जितना संभव हो उतना कम भुगतान करें और मजदूरी का भुगतान अधिनियम, लंबे समय तक काम करना, लाभार्थी द्वारा निषिद्ध खान अधिनियम, कारखाना अधिनियम और इस तरह के क़ानून। ये दोनों जब संयुक्त रूप से अभ्यास किया जाता है तो लाभ बढ़ता है। कानून यह है कि कोई भी नियोक्ता भुगतान नहीं कर सकता है न्यूनतम मजदूरी से कम। कानून यह है कि कोई भी नियोक्ता भुगतान नहीं कर सकता न्यूनतम मजदूरी से भी कम. लेकिन यह तब तक कागजी वादा ही बना रहेगा जब तक कि ऐसा न हो प्रभावी कार्यान्वयन मशीनरी इन अमीरों से भयभीत नहीं है और आम तौर पर

बेईमान ठेकेदार जो अपना जाल फैला सकते हैं अधिकारियों की स्थापना की गई है। अधिकारियों का गठन किया गया है। [133 एच; 134 ए-बी; डी]

(अदालत ने उम्मीद जताई कि इस तरह की मशीनरी भारत संघ और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की जाएगी।) [134 ई]

2. अनुच्छेद 38,41,42 और 43 के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए राज्य को इन गरीब और जरूरतमंद और असुरक्षित श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो समानता की शर्तों पर बातचीत करने में असमर्थ हैं और जो भूख और अभाव को रोकने के लिए किसी भी शर्त को प्रतिग्रहण करना कर सकते हैं।यह राज्य है जिसे शोषण से बचने के लिए इन दोनों असमानताओं के बीच हस्तक्षेप करना चाहिए। [134 बी-सी]

मौलिक क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 1232/1982।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

मुकेश आडवाणी याचिकाकर्ता। (मौजूद नहीं है)

प्रत्यर्थी के लिए ए.वी. रंगम, रवींद्र, बाना, ए.के. सांघी, सुश्री एच. खातून और आर.एन. पद्दार।

न्यायालय का निर्णय देसाई, जे. द्वारा दिया गया था।

एक मुकेश आडवाणी, इस न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ता ने 23 सितंबर, 1982 को इस न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक को संबोधित किया, जिसमें मध्य प्रदेश के रायसेन में पत्थर की खदानों में काम करने वाले बंधुआ श्रमिकों की

भयावह दुर्दशा को दर्शाते हुए 14 सितंबर, 1982 के 'इंडियन एक्सप्रेस' से एक कटिंग को जोड़ा गया था।

मोटे तौर पर आरोप लगाए गए थे कि खदानों का संचालन करने वाले ठेकेदार तमिलनाडु से श्रम बल की भर्ती करते हैं। काम करने के लिए भर्ती किए गए सभी लोगों को लगभग रुपये 1,000 का अग्रिम भुगतान किया जाता था और फिर खदानों में काम करने के लिए लाया गया। यह राशि रु.1,000 बंधुआ मजदूरों को देय मजदूरी से महीने-दर-महीने कटौती द्वारा की प्रतिपूर्ति की जाती है, लेकिन लेखांकन की विधि में इतना हेरफेर किया जाता है कि 1,000 रु का कभी सफाया नहीं होता है, और इसके विपरीत यह ज्यामितीय अनुपात से बढ़ता है। श्रमिक ऋण के दलदल में गहराई तक जाता है जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार की ऑक्टोपस पकड़ पूरी तरह से घेर लेती है और श्रमिक एक बंधुआ श्रमिक बन जाते हैं। कम से कम कहने के लिए, काम करने की परिस्थितियाँ 18 वीं शताब्दी की थीं। कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं है। स्वच्छता की स्थिति दयनीय स्थिति में है। बरसात के मौसम में खदानों का संचालन बंद हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को मजदूरी नहीं दी जाती है। श्रम कल्याण के लिए बनाए गए एक भी कानून को लागू या सम्मानित नहीं किया जाता है। कोई भी कर्मचारी तब तक नौकरी नहीं छोड़ सकता जब तक कि पूरा ऋण चुका नहीं दिया जाता जो श्रमिकों की पहुंच से बाहर है। ठेकेदार के चंगुल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि कर्मचारी मालिक को बदल दे जो एक कागजी अग्रिम द्वारा पूर्व ठेकेदार को भुगतान करता है और चक्र को दोहराया जाता है। यह आरोप लगाया गया था कि केंद्र और राज्य के श्रम विभाग के पदाधिकारी अपनी ओर से सक्रिय सहयोग नहीं होने पर भी पूरी तरह से निष्क्रिय होकर श्रमिकों के शोषण में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि खदानों में कार्यरत श्रम बल के लिए न्यूनतम मजदूरी

निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की अनुपस्थिति में में भुगतान कम और कम है और श्रमिकों का नग्न और निर्लज्ज शोषण किया जाता है।

सामाजिक कार्रवाई मुकदमे के हिस्से के रूप में इस पत्र को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के रूप में माना गया था और 7 अक्टूबर, 1982 के आदेश द्वारा उपायुक्त/कलेक्टर, भोपाल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया था।जिला न्यायाधीश भोपाल को रायसेन में पत्थर की खदानों के स्थल पर जाने और बंधुआ श्रमिकों के अस्तित्व का पता लगाने और खदानों में काम करने की स्थितियों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। एक और निर्देश दिया गया कि जिला न्यायाधीश श्री एन. के. सिंह की सहायता ले सकते हैं जिन्होंने 'इंडियन एक्सप्रेस' में बंधुआ मजदूरी की दुर्दशा को उजागर और चित्रित किया था। कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने वाली समिति को जिला न्यायाधीश के अपने कार्यों को पूरा करने के खर्च को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक के पास रु 1000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था।

उपरोक्त आदेश के अनुसार, जिला न्यायाधीश ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह बताया गया कि तमिलनाडु से भर्ती किए गए श्रम बल ने 24 मई, 1980 को मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के सचिव से शिकायत की थी कि खदान ठेकेदार (अब्दुल रहमान) सुरई खदानों में काम करने वाले तमिल मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था। इस शिकायत को मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक रायसेन को भेज दिया गया था। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि तमिलनाडु के 48 श्रमिकों को रिहा कर दिया गया है और वे तमिलनाडु लौट आए हैं। 8 सितंबर, 1980 को सात श्रमिकों द्वारा पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिनमें से छह तमिलनाडु के थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि खदान ठेकेदार (हामिद

खान) यह दावा करके उन्हें परेशान कर रहा था कि प्रत्येक को 15,000 रु से 16,000 रु उनके द्वारा लिए गए। यह पता लगाना संभव नहीं था कि इतनी बड़ी राशि कैसे जुटाई गई।एक अतिरिक्त शिकायत यह थी कि श्रमिकों को भर्ती के समय सहमति से कम भुगतान किया जाता था और जब भी विरोध की आवाज उठाई जाती थी तो श्रमिकों को शारीरिक रूप से श्रम दिया जाता था। यह आरोप लगाया गया था कि उनकी गतिविधियों को सीमित किया गया था और वे नौकरी छोड़ने या निवास स्थान से दूर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे।संक्षेप में वे एक बंदी जीवन जीते थे। जिला न्यायाधीश ने बताया कि इस शिकायत पर पुलिस स्टेशन में बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत एक अपराध दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के समय मामला लंबित था।जाँच के दौरान जिला न्यायाधीश को जिस दुविधा का सामना करना पड़ा, उसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया जब उन्होंने बताया कि जब कर्मचारी को विश्वास में लिया जाता है और सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है तो वह खदान ठेकेदार द्वारा उत्पीड़न और यातना की कहानी देता है, लेकिन जब आधिकारिक रूप से पूछताछ की जाती है तो वह आवश्यक खुलासा करने से डरता है। लेकिन इस द्विभाजन के अलावा, जिला न्यायाधीश ने देखा कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने खदान ठेकेदार के खिलाफ 11,000 रुपये की वसूली के लिए दो मामले दर्ज किए और कम भुगतान के लिए विषम और रिपोर्ट के समय मामले लंबित थे।

जिला न्यायाधीश ने आगे बताया कि मजदूरी का भुगतान करने का एक टुकड़ा दर तरीका है। टुकड़े की दर 10 रुपये से लेकर है 20 रु से एक मानक 'खांटी' के लिए जो आकार 10 'x10' x1 '(गहराई) का है। एक पुरुष और एक महिला की जोड़ी को 'खांटी' के लिए नियुक्त किया जाता है और एक कठिन दिन की मेहनत के बाद औसत कमाई 5 रु से 10 रु प्रति दिन जिसमें से अनधिकृत और अस्वीकार्य कटौती की जाती

है, जिससे कर्मचारी को जीवित रहने के लिए बहुत कम छोड़ दिया जाता है। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ भी न कमाने की संभावना उतनी ही अधिक थी जितना कि 'खांटी' खोदे जाने के बाद, फ्लैगस्टोन दिखाई देता है और उस पत्थर को निर्दिष्ट आकार के स्लैब में अच्छी तरह से काटा जाता है। यदि पत्थर से स्लैब को ठीक से नहीं काटा जाता है, तो कारीगर को कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता है। कुल कमाई श्रमिक द्वारा काटे गए स्लैब की संख्या पर भी निर्भर करती है। आमतौर पर लगभग 2 रु प्रति दर घन फुट है। हालांकि श्रम विभाग का विचार था कि अनौपचारिक रूप से एक कर्मचारी 650 रुपये प्रति पखवाड़े कमा सकता है, व्यवहार में यह एक कागजी आंकड़ा दिखाया गया था।

जिला न्यायाधीश द्वारा की गई पूछताछ पर, ठेकेदार ने स्वीकार किया कि प्रत्येक कर्मचारी को अग्रिम भुगतान किया जाता है और भुगतान के समय प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी से कटौती करके इसकी वसूली की जाती है। यह भी पता चला कि तमिलनाडु के श्रमिकों को इतना परेशान किया गया था कि तमिलनाडु सरकार को मिली शिकायत पर, पुलिस बल की एक टीम तमिलनाडु से आई, श्रमिकों को मुक्त कराया और उन्हें तमिलनाडु वापस भेज दिया।

जिला न्यायाधीश ने यह भी पाया कि श्रमिकों को नौकरी छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन एक बार जब एक खदान ठेकेदार ने विस्तृत जांच के अधीन होने पर, उसके द्वारा किए गए अग्रिम की वसूली के लिए कोई भी दावा छोड़ दिया, तो प्रतिबंध इस परिणाम के साथ गायब हो गए कि जिला न्यायाधीश के अनुसार, जांच के प्रासंगिक समय पर, कोई बंधुआ श्रम नहीं था।

जिला न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि समाचार पत्र के प्रचार का बहुत ही लाभकारी और वांछित प्रभाव पड़ा है क्योंकि विभिन्न ठेकेदारों ने अग्रिम राशि की वसूली

के प्रयास छोड़ दिए हैं और जिला न्यायाधीश के अनुसार यह एक अच्छी उपलब्धि थी। इस बात का ध्यान दें रखा जाता है कि यदि जिला सतर्कता समिति और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती है कि खदान ठेकेदार जो तब वैध निर्वहन का प्रमाण देने वाले दस्तावेजों को निष्पादित किए बिना श्रमिकों के अग्रिम ऋणों को छोड़ने की मौखिक घोषणा कर रहे थे, तो ऋणों के निर्वहन पर वापस जाने का एक भयावह प्रयास किया जा सकता है और कोई व्यक्ति पहले वर्ग में लौट सकता है।

जिला न्यायाधीश की अनुपस्थिति में यह भी बताया कि इकी अनुपस्थिति में खदाकी अनुपस्थिति मे पर लागू श्रम की अनुपस्थिति में के कार्याकी अनुपस्थिति मेंवयकी अनुपस्थिति में का पूर्ण अभाव है। यह बताया गया कि चूंकि केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है, इसलिए उसने द्वितीय जिले के लिए केवल एक निरीक्षक नियुक्त किया है, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों के लिए लाभकारी कई कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है। एक स्पष्ट मामला यह बताया गया कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधान कुछ खदानों पर लागू होंगे, लेकिन इसके कार्यान्वयन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

जिला न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा संकेतित अनुवर्ती कार्रवाई से श्रमिकों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी और काम करने की स्थितियों में सुधार होगा।

मध्य प्रदेश राज्य ने अपने जवाबी-हलफनामे में विद्वान जिला न्यायाधीश के निष्कर्षों को व्यापक रूप से स्वीकार किया और यह बताया गया कि पत्थर की खानों के संबंध में, उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है। यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

जैसा कि जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट से पता चला कि उत्पीड़न और यातना की शिकायत करने वाले श्रमिकों को पहले ही रिहा कर दिया गया था और संबंधित समय पर कोई बंधुआ श्रम नहीं था, न्यायालय ने श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए निर्देश देने पर ध्यान केंद्रित किया।इस संबंध में न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी के वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन को उच्च प्राथमिकता दी जो खदान ठेकेदार को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा और जो साथ ही न्यूनतम से कम भुगतान करके अनधिकृत कटौती या शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने 23 नवंबर, 1982 के अपने आदेश द्वारा तमिलनाडु राज्य और भारत संघ पर याचिका के नोटिस देने का निर्देश दिया।

तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण विभाग के आयुक्त और सचिव तिरुमती जे. अंजनी दयानंद ने इस अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब में एक शपथ पत्र दायर किया। उसमें पाठ रक्तरंजित होते हैं। यह बताया गया कि तमिलनाडु पुलिस के संज्ञान में तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से मध्य प्रदेश में अनपढ़ ग्रामीण गरीबों के परिवारों को आकर्षक पारिश्रमिक पर आकर्षक रोजगार प्रदान करने की आड़ में अपहरण करने और फिर उन्हें रायसेन और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में अवैध रूप से बंधुआ मजदूरी के रूप में सीमित करने की घटनाएं आईं। इसके बाद पुडुकोट्टई से एक पुलिस दल ने रायसेन का दौरा किया और जुलाई 1982 के दौरान 5 महिलाओं सहित 2 व्यक्तियों को बचाया। पुलिस ने पाया कि श्रमिकों को बंधन में रखा गया था और भोजन और आश्रय के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं था और उन्हें जबरन हिरासत में लिया गया था और उनके मेल के साथ छेड़छाड़ करके उनके रिश्तेदारों के साथ संवाद करने से प्रभावी ढंग से रोका गया था।मामले में पूछताछ करने गए पुलिस कर्मचारियों के साथ खदान ठेकेदारों ने प्रतिकूल व्यवहार किया।एक अन्य पुलिस दल ने 20 अगस्त, 1982 को रायसेन का

दौरा किया और रायसेन जिले में खदानों से 6 परिवारों की 8 महिलाओं सहित 20 लोगों को बचाया।यह पता चला कि तमिलनाडु के ए. एल. सुब्रमण्यम और चोक्कलिंगम ने अपने रिश्तेदारों की सहायता से और खदान ठेकेदारों के साथ मिलकर व्यवस्थित रूप से रोजगार की गुलाबी तस्वीर खींचते हुए भोली-भाली गरीब लोगों को लुभाने और फिर उनका शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करने के इस व्यापार को चलाया।अंततः दो पुलिस निरीक्षकों, 3 उप-निरीक्षकों, 2 हेड-कांस्टेबलों और अपराध शाखा, सी. आई. डी. के 2 पुलिस कांस्टेबलों की एक टीम को मदुरै से सशस्त्र एस्कॉर्ट पार्टी की सहायता से पुलिस उप महानिरीक्षक, सी. आई. डी. अपराध शाखा मद्रास से मध्य प्रदेश में अपने समकक्ष को एक अर्ध-आधिकारिक पत्र के साथ प्रतिनियुक्त किया गया, जिसमें गुलामी के इस प्रकोष्ठ को तोड़ने में सहायता की मांग की गई थी।हमें आगे इस भयावह विवरण का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंततः यह बताया गया कि इन श्रमिकों को रिहा करने के बाद यह पता चला कि अमानवीय खदान ठेकेदारों ने उनका खून सफेद कर दिया था।पूर्ण शोषण का शिकार होने के कारण, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। पुनर्वास के लिए प्रति परिवार 1,000 रुपये और शपथ पत्र की तारीख तक 63,000 रुपये खर्च किए गए।

18 फरवरी, 1983 के हमारे आदेश द्वारा भारत संघ को निर्देश दिया गया था कि वह फ्लैगस्टोन खदानों में विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए ठोस कदम उठाए और इन खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की जीवन शैली में सुधार के लिए प्रभावी कदमों का सुझाव दे।

चूंकि प्रगति धीमी गति की खबरों के समान थी, श्री के. जी. भगत, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए और हमें आश्वासन दिया कि भारत संघ

श्रमिकों की मदद करने और आवश्यक अनुवर्ती कदम उठाने के लिए हर संभव सहयोग करेगा।

जैसे-जैसे मामला बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ा, न्यायालय ने उपयुक्त सरकार के रूप में भारत संघ को खंड के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।5 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए अपना प्रस्ताव निर्धारित किया गया है और अधिसूचना की तारीख से कम से कम दो महीने की तारीख निर्दिष्ट की गई है, जिस पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

कई बार स्थगन लेने के बाद, श्रम विभाग में भारत सरकार के अवर सचिव, बिशंबर नाथ ने भारत संघ की ओर से जवाब में अपना शपथ पत्र दायर किया, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि धारा के तहत अधिसूचना जारी करने का प्रश्न श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।यह भी बताया गया कि चूंकि न्यूनतम मजदूरी टुकड़ों में मिलने वाली मजदूरी होने की संभावना है, इसलिए एक समिति नियुक्त करना या प्रस्तावों का पूर्व प्रकाशन करना आवश्यक हो सकता है। यह कहा गया था कि कुछ डेटा एकत्र किया जाना है और इस उद्देश्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों की एक टीम को आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए रायसेन भेजा जा रहा है। 26 सितंबर, 1983 को जब यह मामला इस अदालत के समक्ष आया, तो भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री गुजराल ने एक बयान दिया कि नवंबर, 1983 के पहले सप्ताह के अंत तक एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाएगी।भारत संघ ने वादा की गई कार्रवाई की और 31 अक्टूबर, 1983 की एक प्रारंभिक अधिसूचना को रिकॉर्ड में रखा गया। अधिसूचना की अनुसूची फ्लैगस्टोन खदानों में विभिन्न व्यवसायों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर अनुसूची करती है। 16

अप्रैल, 1980 को भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा 24 मार्च, 1982 को जारी अधिसूचना की एक प्रति अदालत को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें फ्लैगस्टोन खदानों में विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट की गई थी। धन शक्ति के कारण गरीबों और जरूरतमंदों का शोषण करने वाले व्यक्ति द्वारा शोषण से बचने के लिए एक जोरदार अभियान के हिस्से के रूप में उठाया जाने वाला पहला कदम यहीं समाप्त होता है।यह यात्रा का अंत नहीं है।यह सिर्फ एक शुरुआत है।

इस याचिका का अब निपटारा किया जाना चाहिए क्योंकि इस फैसले के पहले भाग में संदर्भित जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि रायसेन में फ्लैगस्टोन खदानों में कोई बंधुआ श्रम काम नहीं कर रहा है।

निस्संदेह, खदानों को व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में काम करना होगा। इसलिए, चीजों की प्रकृति में, ठेकेदार और श्रमिक होंगे।ठेकेदार जैसा कि उसकी आदत है, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए जो उसे अनुबंध लेने के लिए प्रेरित करता है और जो परोपकारी नहीं दिखाया जाता है, वह श्रमिकों का शोषण करने के लिए बाध्य है। शोषण का कुख्यात तरीका है, न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी भुगतान अधिनियम के सभी ढोंगों के बावजूद जितना संभव हो उतना कम भुगतान करना, लंबे समय तक काम करना, जो खान अधिनियम, कारखाना अधिनियम और इस तरह के कानूनों जैसे लाभकारी कानूनों द्वारा निषिद्ध है। इन दोनों का जब संयुक्त रूप से अभ्यास किया जाता है तो लाभ बढ़ जाता है। कला के तहत अपने दायित्व के निर्वहन में राज्य 38, 41, 42 और 43 को इन गरीब और जरूरतमंद और असुरक्षित श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो समानता की शर्तों पर बातचीत करने में असमर्थ हैं और जो भूख और अभाव को दूर करने के लिए किसी भी शर्त को प्रतिग्रहण करना कर सकते हैं। यह राज्य है जिसे शोषण से बचने के लिए इन दोनों असमानताओं के बीच हस्तक्षेप करना चाहिए।

पहले कदम के रूप में, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी की गई है। जिस कानून को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वह यह है कि कोई भी नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं कर सकता है। लेकिन यह एक कागजी वादा बना हुआ है जब तक कि इन अमीर और आम तौर पर बेईमान ठेकेदारों द्वारा एक आक्रामक कार्यान्वयन तंत्र स्थापित नहीं किया जाता है जो अधिकारियों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। हम इस उम्मीद के साथ समापन करते हैं कि भारत संघ और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस तरह की मशीनरी की स्थापना की जाएगी। इन टिप्पणियों के साथ, याचिका का निपटारा हो जाता है।

एस.आर.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।